BSNL EMPLOYEES UNION

Recognised Union in BSNL
(Registered Under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No.4896)
CHQ:Dada Ghosh Bhawan, Opp. Shadipur Bus Depot., New Delhi – 110008
Email: bsnleuchq@gmail.com, website: bsnleu.in

P. Abhimanyu
General Secretary

Phone: (O) 011-25705385
Fax : 011- 25894862

Dated: 26.06.2019

प्रेस विज्ञप्ति

बीएसएनएल मैनेजमेंट द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स को 17 जून, 2019 को लिखे गए पत्र की वजह से उत्पन्न कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट करने के लिए बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन (BSNLEU) द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है। उक्त पत्र में BSNL मैनेजमेंट द्वारा कहा गया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और बगैर तत्काल आर्थिक सहयोग के, कर्मचारियों को जून 2019 के वेतन भुगतान के साथ साथ कंपनी का संचालन जारी रखना भी कठिन होगा। इस पत्र के आधार पर मीडिया में कई रिपोर्ट्स परिलक्षित हुई है, जो कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी दिग्भ्रमित कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट ने तो BSNL के ग्राहकों को अन्य कंपनी की सेवाएं लेने तक की सलाह दे डाली है।

केवल BSNL ही नही, वरन सम्पूर्ण टेलीकॉम सेक्टर ही गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में है। रिलायंस जियो द्वारा अपनाई गई लागत से कम मूल्य निर्धारण (प्रिडेटरी प्राइसिंग) की वजह से यह सेक्टर कई प्रकार के वित्तीय संकट से ग्रसित है। सितंबर 2016 से अपनी सेवाओं की शुरुआत के साथ ही जियो द्वारा लागत से काफी कम मूल्य पर सेवा प्रदान की जा रही है। रिलायंस जियो, जो वित्तीय रूप से बेहद शक्तिशाली है, द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के उद्देश्य से यह रणनीति अपनाई गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और ट्राई के द्वारा जियो को पूर्ण रूप से अघोषित सहयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप BSNL सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों के राजस्व अर्जन में तीव्र गिरावट आई है। रिलायंस जियो द्वारा शुरू किए गए नृशंस मूल्य युद्ध की वजह से एयरसेल, टाटा टेली सर्विसेस, अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फो और टेलीनॉर जैसी कंपनियां बंद हो चुकी है।

जो BSNL की दक्षता (efficiency) की बात करते हैं, उन्हें यह नही भूलना चाहिए कि इसी BSNL ने एक लाख से अधिक कर्मचारी होने के बावजूद सन 2004-05 में रु 10,000 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। किंतु, इसके बाद, यूपीए सरकार ने 7 वर्षों तक अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए BSNL को अनुमति नही दी थी। BSNL द्वारा जारी टेंडर्स एक के बाद, निरस्त कर दिए गए। इससे BSNL की प्रगति में व्यापक रूप से अवरोध उत्पन्न हुआ।

उपर्युक्त उल्लेखित तमाम अन्तर्ध्वंस (sabotage) के बावजूद BSNL रिलायंस जियो के प्रवेश तक बेहतर रूप से परफॉर्म कर रहा था। वित्तीय वर्ष 2014-15 पश्चात, BSNL निरंतर रूप से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अर्जित कर रहा था। स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2015 में किए गए अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी गर्व के साथ उल्लेखित किया था कि BSNL ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्जित करना शुरू कर दिया है।

वर्तमान वित्तीय परेशानियों के बावजूद, BSNL अपने मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रहा है। उदाहरण के लिए 2017-18 में BSNL के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में 11.5% की वृद्धि हुई, जबकि एयरटेल के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में केवल 9.5% का इजाफा हुआ, वहीं वोडाफोन में 3.8% की और आईडिया में 3.2% की ही वृद्धि हुई। अप्रैल 2019 में भी BSNL ने 2,32,487 नए मोबाइल ग्राहक जोड़े, जबकि एयरटेल ने अपने 29,52,209 मोबाइल ग्राहक खोए और वोडाफोन आईडिया को भी उसके 15,82,142 मोबाइल उपभोक्ता खोना पड़े।

यदि आर्थिक स्थिति की भी बात करें, तो BSNL की स्थिति निजी ऑपरेटर्स की तुलना में ज्यादा खराब नही है। आज दिनांक तक BSNL पर केवल रु 13,000 करोड़ का ही ऋण है। जबकि वोडाफोन आईडिया पर रु 1,18,000 करोड़ और एयरटेल पर रु 1,08,000 का कर्ज है। इतना ही नही, रिलायंस जियो पर भी रु 1,12,100 करोड़ की बड़ी राशि का ऋण है।

साथ ही, BSNL का वित्तीय आधार भी व्यापक रूप से मजबूत है। उसके पास 7.5 लाख रूट किलोमीटर्स का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। जबकि रिलायंस जियो का OFC नेटवर्क मात्र 3.5 लाख रूट किलोमीटर्स है, एयरटेल का OFC नेटवर्क 2.5 लाख रूट किलोमीटर्स और आईडिया वोडाफोन का OFC नेटवर्क 1.60 लाख रूट किलोमीटर्स है। BSNL के पास देशभर में रिक्त पड़ी जमीन की कीमत रु 1 लाख करोड़ आंकी गई है। अन्य किसी भी कंपनी के पास इतनी विशाल संपदा नही है।

ऊपर उल्लेखित मजबूत स्थिति के बावजूद आज BSNL नगदी की भीषण किल्लत से जूझ रहा है। यह टेलीकॉम सेक्टर में वर्तमान में व्याप्त तनाव की वजह से है। BSNL का शतप्रतिशत स्वामित्व भारत सरकार का है। कंपनी की मालिक होने के नाते यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह BSNL की अल्प और दीर्घ समयावधि की पूंजी की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। यह कहना जरा भी अतिशयोक्तिपूर्ण नही होगा कि, विगत साढ़े अठारह वर्षों की अवधि में, BSNL को टैक्स दाताओं की राशि में से एक पैसे का भी आर्थिक सहयोग प्राप्त नही हुआ है।

जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, यह BSNL ही है, जो सरकार के राहत और बचाव कार्य मे सहयोग करता है। इस दौरान अन्य सभी निजी ऑपरेटर्स अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। इसके अलावा, सुदूर और पिछड़े इलाके में रहने वाले लोग भी अपनी संचार की जरूरतों के लिए BSNL पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में, यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह BSNL की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करे।

किन्तु, केंद्र में जो भी सरकार सत्ता में आई, उसने BSNL के साथ सौतेलेपन का नजरिया ही अपनाया। और इस तरह का रवैया आज भी जारी है। उदाहरण के लिए, निजी कंपनियों को मोबाइल सेवाएं प्रदत्त करने के लिए काफी पहले, सन 1995 में लाइसेंस प्रदान कर दिया गया था। किंतु, BSNL, सरकारी सेवा प्रदाता होने के बावजूद, सन 2002 में ही लाइसेंस प्राप्त कर पाया। साथ ही, निजी कंपनियां 5 वर्ष पूर्व से अपनी 4G सेवा शुरू कर चुकी है। लेकिन, सरकार ने अभी तक BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित नही किया है। यह दर्शाता है कि किस तरह सरकार के नीतिगत निर्णयों ने BSNL को विकसित होने में बाधाएं निर्मित की है।

वर्ष 2000 में, BSNL की स्थापना के समय कैबिनेट ने विश्वास दिलाया था कि वह BSNL की वित्तीय सुदृढ़ता का ध्यान रखेगी। किन्तु यह आश्वासन मात्र कागजों तक ही सीमित रहा। दरअसल, BSNL टेलीकॉम इंडस्ट्री में वास्तविक नियामक (regulator) की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केवल BSNL के अस्तित्व में रहने की वजह से ही निजी ऑपरेटर्स टैरिफ में वृद्धि नही कर पा रहे हैं। जैसे ही BSNL का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, निजी ऑपरेटर्स को ग्राहकों की बर्बरता पूर्वक लूट की छूट मिल जाएगी। अतः, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के नागरिकों के हित में और देश हित मे BSNL की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

पी.अभिमन्यु,
जनरल सेक्रेटरी,
बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन,
मोब.न. 9868231113